RAJYA SABHA

Wednesday, 23rd August, 1995/1 Bhadra, 1917 (Saka)

The House met at the Eleven of the Clock, Mr. Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Allotment of Forest Land to private parties for Development

*281. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the criteria for allotment of forest land to private parties for development;

(b) whether revenue is collected on such land by State Government;

(c) if so, the details thereof;

(d) the forest land to be given to private parties for development in Gujarat State during 1995-96; and

(e) the revenue likely to be collected therefrom?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No forest land is allotted to private parties for its development.

(b) to (e) Do not arise.

श्री राजूभाई ए० परमार: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन भूमि के विकास के लिए इंडस्ट्रीयल हाऊसेज़ को इनवाल्व करने के लिए कोई प्रोपोज़ल केबीनेट में मंजूरी के लिए लाया गया था या नहीं, यदि हां तो इसका क्या ब्यौरा है? क्या मिनिस्ट्री में कोई सब कमेटी का प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गठन किया गया था या नहीं यदि हां तो इसकी क्या कार्यवाही है? ऐसे इंडस्ट्रीयल हाऊसेज़ को जमीन का अलॉटमेंट करने के लिए क्या कोई एम०ओ०यू० किसी इंडस्ट्रीयल हाऊस के साथ साइन किया गया था या नहीं, यदि हां तो ऐसे कौन कौन से औद्योगिक घराने हैं जिनके साथ ऐसे एम०ओ०यू० साइन किये गये और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं?

श्री कमल नाथ: महोदय, जहां तक इंडस्ट्रीयल हाऊसेज़ को वन्यकरण में सम्मिलित करने का प्रश्न है, राज्य सरकारों के कुछ प्रस्ताव थे। फॉरेस्ट कंज़रवेशन एक्ट और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अन्तर्गत राज्य सरकारों और उनकी स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशंस को कुछ अधिकार हैं जिनका वह उपयोग कर सकती है। उनके लिए चूंकि कई राज्य ऐसा करना चाहते थे इसलिए हमने यह सोचा कि मंत्रालय को गाइडलाईंस बनाने की आवश्यकता है ताकि एक राज्य और दूसरे राज्य में समन्वय और बैलेंस बना रहे और ऐसा न हो कि एक राज्य सरकार कुछ कर रही है और दूसरी राज्य सरकार कुछ और कर रही है। यह गाइडलाईंस जो हम तैयार कर रहे थे इन गाइडलाईंस की स्वीकृति के लिए मैंने केबीनेट में एक प्रस्ताव रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक केबीनट कमेटी ग्रुप आफ मिनिस्टर्ज की बनाई है जो इस पर अभी विचार कर रही है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या ऐसा कोई एम०ओ०यू० किसी इंडस्ट्रीयल हाऊस के साथ हुआ है, यह केन्द्र सरकार का प्रश्न नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार कोई एम०ओ०यू० इंडस्ट्रीयल हाऊस से नहीं करेगी और न कर सकती है। राज्य सरकार के जो वन निगम है, स्टेट फॉरेस्ट डवलपमेंट कारपोरेशंस हैं, वह भविष्य में किस प्रकार से इंडस्ट्रीयल हाऊसेज़ या अन्य संस्थाओं से समझौता करेंगे, इसके लिए ही गाइडलाईंस बनाई जा रही हैं।

श्री राजूभाई ए० परमार: माननीय सभापति महोदय, गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में वन भूमि के विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में अब तक ऐसी किसी वन भूमि का अलॉटमेंट नहीं किया गया है लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक राज्य में स्थापित किये गये साल्ट, लाइम स्टोन, बैंटानाइट व अन्य प्रकार के माइनिंग उद्योग के लिए राज्य सरकार द्वारा कच्छ, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ जैसे जिलों में भूमि का अलॉटमेंट प्राइवेट पार्टीज़, अनिवासी भारतीयों तथा मल्टीनेशनल कम्पनीज़ को भारी संख्या में किया गया है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पिछले 6 महीने में देश के कुछ निजी औद्योगिक घरानों को राज्य में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए और इस भूमि पर माइनिंग के लिए आमंत्रित किया है। क्या राज्य सरकार ने इस भूमि का अलॉटमेंट करने से पूर्व केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति मांगी थी, यदि हां तो केन्द्र सरकार ने इसके बारे में क्या डिसिज़न लिया है? यदि नहीं तो केन्द्र सरकार इसके बारे में क्या करने जा रही है?

श्री कमल नाथः सभापति महोदय, सन् 1980 में फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट आया। उसके पहले कई प्रकार की माइनिंग गुजरात राज्य में हो रही थी खास कर के साल्ट माइनिंग। सन् 1980 के फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के बाद यह दायित्व था राज्य सरकार का जो भी लीज़ थी उनके रिन्यूअल के पहले या नयी लीज़ देने के पहले फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के अनुसार केन्द्र सरकार की स्वीकृति ले। गुजरात राज्य ने ऐसी कुछ लीज़ को रिन्यू किया है बिना केन्द्र सरकार की स्वीकृति लिए हुए **(व्यवधान)**

SHRI JAGESH DESAI: Without permission!

SHRI KAMAL NATH: Yes, without permission.

इसका कुछ कारण भी था। उन्होंने बताया कि उनको सही जानकारी नहीं थी। इंटरप्रिटेशन में भी कुछ ऐबिग्युटी थी कि रिन्यूअल के लिए स्वीकृति लें या नयी लीज़ के लिए स्वीकृति लें। अब यह मामला स्पष्ट हो गया है। कोर्ट का भी फैसला आया है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। साल्ट लीज़ को रिन्यू करने या उनको साल्ट लीज़ देने के। जहां तक प्रश्न है राज्य सरकार ने अगर किसी को आमंत्रित किया है माइनिंग के लिए प्रदेश में, अगर यह वन भूमि पर है तो फॉरेस्ट कंज़रवेशन एक्ट में उनकी स्वीकृति कोई लीज़ या कोई काम शुरू करने से पहले उनको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारे इनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो नियम हैं, उनके अनुसार अगर आवश्यकता हो तो उनका भी पालन करना होगा। लेकिन यह लीज़ पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ की माइनिंग है। अगर इनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में उनकी स्वीकृति लेनी हो तो कुछ भी करने से पहले, कोई समझौता करने से पहले, कोई लीज़ करने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले, उनको केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है।

श्री राजूभाई ए॰ परमारः सभापति महोदय, अभी कुछ ज़िलों के अन्दर माइनिंग के लिए सांघी सीमेंट को जो एक सेंक्चुरी का जो वन था उसमें से आधी से ज्यादा लैंड दे दी गई है। माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सांघी सीमेंट को जो सेंक्चुरी की लैंड थी वह दी गई, क्या इसके बारे में कोई परमिशन केन्द्र सरकार से मांगी ग थी या नहीं? इसके बारे में केन्द्र क्या सोच रही है?

श्री कमल नाथः सभापति महोदय, सांघी सीमेंट द्वारा वन भूमि पर माइनिंग के लिए अभी तक कोई प्रोपोज़ल केन्द्र सरकार को नहीं दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है करीब एक-डेढ़ महीना पहले राज्य सरकार ने पहली दफा अपने देश के इतिहास में एक सेंक्चुरी के बार्डर में परिवर्तन करते हुए एक प्रसिद्ध सेंक्चुरी के बार्डर घटाए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो नियम है, उनके अनुसार प्रावधान तो है परन्तु प्रावधान होने का यह मतलब नहीं है कि इसकी आवश्यकता है। यह पहली दफा अपने देश के इतिहास में इस प्रकार सेंक्चुरी के बार्डर चेंज किये गये हैं। कहा जाता है कि इस सेंक्चुरी में जो एरिया घटाया गया है उस पर माइनिंग होगी। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है परन्तु सेंक्चरी का जो बार्डर घटाया गया है, वन भूमि के बार्डर को घटाया नहीं जा सकता है। वन भूमि के माइनिंग का प्रस्ताव कि कोई कम्पनी उस पर माइनिंग करना चाहेगी, इस प्रकार का कोई प्रोपोज़ल अभी तक राज्य सरकार से नहीं आया है। **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंहः सभापति जी, पर्यावरण का मामला पूरे विश्व का मामला बन चुका है। इस देश में करीब ढाई करोड़ हेक्टेयर जमीन हमारे पास ऐसी है जहां जंगल नहीं है करीब करीब बंजर भूमि के रूप में है। सन् 1988 में भारत की सरकार ने उस समय के एक बड़े नामी-गिरामी सचिव के दबाव में एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी।

उस फारेस्ट पालिसी पर संसद में न तो कभी बहस की गई और न कभी हम लोगों ने चर्चा की। राज्य सरकारों ने उस पालिसी को मानने से इंकार कर दिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां एक ओर आपके पास इतनी बंजर भूमि पड़ी है। सारी दुनिया में, आप देखिए बरसात भी कम हो रही है इसकी वजह से। जंगल हमारे हमेशा कटते जा रहे हैं और बंजर भूमि की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो आप एक तो यह बताने की कोशिश करें कि इन ढाई करोड़ हैक्टर बंजर भूमि पर आप जंगल लगाने के कौनसे उपाय कर रहे हैं और चूंकि राज्य सरकार का यह विषय है वन, उनको आप कैसे विश्वास में लेना चाह रहे हैं? दूसरी बात, सन 1988 की जो फॉरेस्ट पालिसी है, क्या उस फारेस्ट पालिसी को आप संसद में कभी रखेंगे? क्या उस पर कभी हम लोगों से बहस, चर्चा कराने का काम करेंगे? और, जो राज्य सरकार की असहमति है उस पालिसी के ऊपर, उस निति के ऊपर, उनको आप कैसे विश्वास में लेंगे? यह मेरे "ए" और "बी" दो सवाल हैं, इनका आप जवाब दे दें।

श्री कमल नाथः सर, 1988 में नेशनल फारेस्ट पालिसी बनी थी। यह नेशनल फारेस्ट पालिसी कैबिनेट ने उस समय 1988 में स्वीकार कर ली थी। यह उस समय संसद की लाइब्रेरी में ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंहः संसद को छोड़कर इसे आपने लाइब्रेरी में रखवाया? आखिर हम सारे लोग यहां किस लिए बैठे हुए हैं? चर्चा के लिए ही बैठे हैं। यह नीतिगत सवाल है।

श्री कमल नाथः सर, 1988 में जो फारेस्ट पालिसी बनी थी, उस फारेस्ट पालिसी पर बहुतों से विचार किया गया था और यह बात सही है कि संसद में इसकी बहस नहीं हुई। नेशनल फारेस्ट पालिसी एक ऐसी नीति है, जिससे देश की आम जनता संबंधित है। अगर माननीय सदस्य चाहें और आपका आदेश हो कि इस नेशनल फारेस्ट पालिसी पर संसद के दोनों हाउसेस में इसकी बहस हो तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री दिग्विजय सिंहः हम तो जरूर चाहेंगे।

श्री कमल नाथः सर, जहां तक प्रश्न है राज्य सरकारों का, कुछ राज्य सरकारों ने इस के कुछ मुद्दों पर असहमति व्यक्त की है और इस पर उनसे चर्चा हो रही है। जहां तक प्रश्न ढाई करोड़ हैक्टेयर डीग्रेडेड फारेस्ट लैंड का है, माननीय सदस्य की बात सही है कि साढ़े छह करोड़ हैक्टर हमारा रिकार्डेड फारेस्ट लैंड है, उसमें से ढाई करोड़ हैक्टर डीग्रेडेड है, जिस पर कोई वन नहीं है। यह एक चिंता का विषय है और इसी संदर्भ में, कि ढाई करोड़ हैक्टेयर का वनीकरण कर पाएं, मैंने गाइडलाइन, हमारे मंत्रालय ने गाइडलाइन बनाई हैं, जिस पर कैबिनेट विचार कर रही है।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः सर, मंत्री जी जवाब छोटा दिया करें। ...(व्यवधान)...

SHRI V.P. DURAISAMY: Thank you, Sir. I want to know from the hon. Minister the measures proposed to be taken by the Central Government in order to preserve ecology of the forest area. The Minister says that in spite of giving the forest land to the private parties, the Central Government would come forward to help the State Forest Corporations financially to take up afforestation.

Secondly, on what grounds is the Government giving the degraded forest area to the private parties?

SHRI KAMAL NATH: Sir, I have not understood the first part of the hon. Member's question, but I will try to answer the second part. There is, up till now, no forest land has been given either on lease or in any way transferred to the private sector or any private party for afforestation. I would like to make it very clear that there is no proposal of the Government to transfer the forest land or lease to any private party or any industrial house. The question which is being considered is whether the State Forest Corporations can take the assistance of the private sector in afforestation without transferring or leasing or handing over to them degraded forest land, that too degraded forest land which has less than 0.1 per cent density where there are no community rights, where there are no fuel and fodder available, which is being subjected to even greater soild erosion, which is being subjected to encroachment—these are the concerns of the State Forest Corporations, the State Governments. We share those concerns. In order to have a uniform policy of the State Governments in this, we decided that there should be guidelines. We should not have one State competing with another State in trying to be liberal in this because the ramifications can be profound. So, in the light of that, the guidelines which have been framed by my Ministry are under the consideration of the Cabinet, for which a Cabinet Committee of a Group of Ministers has been formed.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I am somewhat perplexed by the answer given by the Minister to the question for two reasons. One is that there are many, what we call, forest villages all over the country, and the forest villages are there in Assam, in Jalpaiguri in West Bengal and other places where you have roads, you have schools, you have people living there, but they are not covered by the Panchayat system, nor are they given any recognition in terms of the land rights. There are no land surveys conducted.

There are thousands and thousands of people living all over the country in forest villages which are in a sense recognised because they have got the schools and all that. Still they do not get a proper recognition from the Government in terms of their sending their representatives to the Assembly and Parliament or other places, and having Panchayat elections and all that. I would like to know from the Minister what policies the Government have with regard to the forest villages. And I am sure he is familiar with the term. The other aspect about which I was perplexed is this. At the time of Rajiv Gandhi, there was a lot of discussion on wasteland development, and one of the ideas which came up as a policy was that the degraded forest land should be given over to big business houses, both for producing raw material for their industries and also for producing food for their workers. There was a lot to talk at least at one stage of making such use, and giving it to the industrial houses. Later on, I got the impression that the industrial houses were not interested very much in this proposal. So, that was quietly dropped. The question in whether that policy still continues or not, as far as it was articulated by Rajiv Gandhi, at his time, under this wasteland development scheme because that also covers the degraded forest land.

SHRI KAMAL NATH: Sir, in reply to the first part of the hon. Member's question about forest villages, forest villages are those villages which are in the forest, and they were given a special status because of their logistic location within the forest. They were not called revenue villages and, in fact, the developmental work in these villages was done by the Forest Department. Their roads, their schools and drinking water were provided by the Forest Department, and not by the various other Government Departments. So, some time ago, a policy decision was taken that all these forest villages should be converted into revenue villages. In fact, in different States, there are different scenarios. In Madhya Pradesh, even in our own district, there is a different scenario. There was a feeling in some of the villagers that whereas as forest villages they were a greater beneficiary of the developmental schemes of water, irrigation, etc., if they became a part of the entire revenue village, the gamut of the State Government, perhaps, they would not get the same kind of facilities. It was question of which was better; it was a trade off of one against the other. In different States, there was different scenarios. But we took a policy decision that all forest villages should be converted into revenue villages. This process is now on. In fact, various State Governments have held discussions on this specific issue. We have laid down our guidelines and policies on this because it means transferring the land. Though the land is not with the villagers, they will be allowed to plough on the land, they will be allowed to utilise a part of the land. And even in the case of loans, those villagers are not able to get loans from the various co-operative societies or from various co-operative banks because they do not have any title in their name.

This process of converting forest villages into revenue villages is now on.

With regard to the hon. Member's second question about degraded forest land—degarded land includes degraded forest land—there has been a lot of discussion about this. There are some contrary views on this. Sir, I would draw your attention. You, yourself, made a reference to me on this matter, in connection with some petition which had come to you very recently. Up till now, no industrial house is involved in this. As the hon. Member has said, the degraded forest land in our country is of the order of 2.5 crore hectares, i.e. 25 million hectares. Along with this, there is the current degradation which is taking place. All the resources of the Central and the State Governments are not allowing us to take up this enormous quantity of

degraded forest land for the purpose of afforestation.

Sir, as I said, up till now, no industrial house, excepting an isolated case in Karnataka, is involved in plantation activity. What was discussed several years ago was not finalised and was not formulated. Now, what we are planning today is that the State Forest Corporation may, on certain types of degraded forest land, to the extent of degradation, etc... *(Interruptions)*

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: महोदय, जवाब इस तरह से छोटा दिया जाना चाहिए कि सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकें। जब सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि सवाल छोटा हो, तो जवाब भी छोटा ही होना चाहिए।....(व्यवधान)

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی: مہودے - جواب اس طرح سے چھوٹا دیا جانا چاہئے کہ سوال زیادہ سے زیادہ پوچھا جا سکے - جب سوال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سوال چھوٹا ہو تو جواب بھی چھوٹا ہی ہونا چاہئے - ... "مداخلت" ...]

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this is a very important question. Therefore, the Minister should be allowed to continue. *(Interruptions)*

SHRI AJIT P.K. JOGI: He is explaining the details. अच्छी बात समझा रहे हैं। *(Interruptions)*.

DR. BIPLAB DASGUPTA: The Minister should be allowed to continue. *(Interruptions)*

SHRI KAMAL NATH: Sir, I am happy to answer this question in detail. The question is ....*(Interruptions)*

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: मंत्री जी को सागर को गागर में बंद करने की कला को समझना चाहिए। आप कहते हैं कि सवाल छोटा होना चाहिए तो जवाब भी इतना बड़ा न हो। और लोग भी इस बारे में सवाल कर लेंगे न। .....(व्यवधान)

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی: منتری جی کو ساگر کو گاگر میں بند کرنے کی کلا کو سمجھنا چاہئے - آپ کہتے ہیں کہ سوال چھوٹا ہونا چاہئے تو جواب بھی اتنا بڑا نہ ہو اور لوگ بھی اس بارے میں سوال کر لیں گے نا - ... "مداخلت" ...]

SHRI DIGVIJAY SINGH: These questions are of national and international importance. *(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: Mr. Minister, please continue. Please give the details.

SHRI V. NARAYANASAMY: This concerns the rural people. The hon. Minister is replying about that. The poor and the tribal people are living there. Let us know the details. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please allow the Minister to conclude.

SHRI KAMAL NATH: Sir, no degraded forest land has been given to any industrial house up till now. There are guidelines...

SHRI JAGESH DESAI: What about Gujarat?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sanghi, Gujarat.

SHRI KAMAL NATH: I will answer this question when they put it.

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, it is a very, very serious issue. When, in other areas, the sanctuary land has been extended, it has been reduced here. Take, for example, Sawai Madhopur. When the cement factory was set up, it was within thirty kilometres of the sanctuary and, therefore, it was asked to close down. On the other hand, it has been allowed here. We would like to know about this. It is a very serious question.

---

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

SHRI KAMAL NATH: I appreciate the hon. Member's concern. It is a very valid concern. Sir, only four per cent of our area, only four per cent of the total land mass in the country, is protected. Even if that is reduced, obviously, it is a matter of very serious concern. It is for the first time that such a thing has happened in Gujarat. We have asked for information. Appropriate steps would be taken and, if necessary, I would take the House into confidence on it. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Question No. 282.

Allotment of Distributorships of Petroleum Products without selection by OSB

*282. DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether some distributors for sale of petroleum products have been appointed without selection by concerned Oil Selection Boards during the last three years;

(b) if so, details of such appointments product-wise, district-wise and oil company-wise, separately, in each year;

(c) whether some guidelines have been prescribed for appointment of distributors without selection by Oil Selection Boards; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The number of dealerships/distributorships appointed/commissioned by the oil companies during the last three years i.e. 1992-93, 1993-94 and 1994-95 under discretionary powers of the Government was 327. Company-wise, product-wise break-up is as under:

Company	MS/ HSD	SKO/ LDO	LPG	TOTAL
IOC	38	14	81	133
HPC	17	13	48	78
BPC	23	13	50	86
IBP	26	4	—	30
	104	44	179	327

(c) and (d) According to the guidelines approved by the Supreme Court, effective 1.4.1995, the guiding factors for Government in making discretionary allotments of dealerships/distributorships to persons on compassionate grounds would be as under:

(i) Dependent of a person who has made supreme sacrifice for the nation, but has not been properly rehabilitated so far.

(ii) Member of a family which has been a victim of unforeseen circumstances, like terrorist attack, earth-quake, floods, etc.

(iii) Physically handicapped person.

(iv) Defence/para-military/police personnel/other Central/State Government employees, who are permanently disabled on duty.

(v) Immediate next of kin, namely, widow, parents, children of those who lost their lives in abnormal circumstances.

(vi) Eminent professionals like outstanding sportsmen, musicians, literateurs, etc. and women, of high achievement, in distress.

(vii) Individual cases of extreme hardship, which in the opinion of Government are extremely compassionate and deserve sympathetic consideration in view of the special circumstances of the case at the given time.